

# निवेश जुटाने में ऊर्जा विभाग में दिखी शक्ति, नगर विकास व कृषि पिछड़े

7.16 लाख करोड़ के 8,961 निवेश प्रस्ताव **भूमि पूजन** को तैयार

## यूपीजीआइएस-2023

**13** विभाग जीबीसी लक्ष्य का 50 प्रतिशत भी हासिल नहीं कर सके

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआइएस) में हासिल भारी भरकम निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की होड़ में ऊर्जा विभाग तमाम विभागों को पीछे छोड़ता दिखाई दे रहा है, वहीं नगर विकास विभाग और कृषि सर्वाधिक लचर प्रदर्शन करने वाले महकमों में शुमार किए जा रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) के जरिए एक तिहाई से अधिक निवेश करारों (एमओयू) के भूमि पूजन की तैयारियों में जुटी सरकार द्वारा सहेजे जा रहे आंकड़ों में कुछ ऐसी ही तस्वीर बयां हो रही है। बता दें कि जीआइएस के जरिए प्राप्त होने वाले निवेश प्रस्तावों का आंकड़ा अब बढ़कर 39.52 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

फिलहाल, जीबीसी के पूर्व के तय लक्ष्य 13.10 लाख करोड़ रुपये के सापेक्ष 7.16 लाख करोड़ रुपये के 8,961 एमओयू भूमि पूजन के लिए तैयार हैं। लक्ष्य के सापेक्ष यह उपलब्धि 55 प्रतिशत के करीब आंकी गई है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने जीबीसी लक्ष्य को बढ़ाकर अब 15 लाख करोड़ कर दिया है। नया लक्ष्य इस उपलब्धि को 50 प्रतिशत से कम आंक रहा है। कुल 37 विभागों में से 13 प्रमुख विभागों का

## भूमि पूजन के लिए सर्वाधिक निवेश जुटाने वाले शीर्ष विभाग

विभाग	निवेश लक्ष्य	भूमि पूजन के लिए तैयार निवेश	प्रतिशत
प्राथमिक शिक्षा	63.00	558.00	885.98
प्राविधिक शिक्षा	4,500.00	5,417.00	120.38
ऊर्जा -	37,500.00	39,797.00	106.13
चीनी व गन्ना	1,250.00	1,285.00	102.80
नागरिक उड्डयन	4,000.00	4,000.00	100.00
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	12,500.00	11,492.00	91.94
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत	1,25,000.00	1,07,364.00	85.89

(निवेश लक्ष्य व भूमि पूजन के लिए तैयार निवेश करोड़ रुपये में)

## निवेश जुटाने में फिसड्डी रहे प्रमुख विभाग

विभाग - जीबीसी निवेश लक्ष्य -	भूमि पूजन के लिए तैयार निवेश	प्रतिशत	
नगर विकास	1,25,000.00	2,965.00	2.37
माध्यमिक शिक्षा	563.00	27.00	4.83
कृषि -	3,750.00	356.00	9.49
परिवहन	10,000.00	1,059.00	10.59
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग	31,250.00	4,392.00	14.05
खाद्य आपूर्ति एवं औषधि	8,750.00	1,337.00	15.28

(निवेश लक्ष्य व भूमि पूजन के लिए तैयार निवेश करोड़ रुपये में)

अब तक का प्रदर्शन खासा लचर रहा है। नगर विकास की उपलब्धि तय लक्ष्य के महज 2.37 प्रतिशत तक सीमित है। माध्यमिक शिक्षा की 4.83 प्रतिशत और कृषि विभाग 9.49 प्रतिशत के दायरे तक सीमित रहा है। वहीं, ऊर्जा विभाग तय लक्ष्य से कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हुए 106 प्रतिशत निवेश को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्राविधिक शिक्षा, चीनी एवं गन्ना और नागरिक उड्डयन विभाग

100 प्रतिशत उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। निवेश लक्ष्य के लिहाज से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। इस विभाग के 1.07 लाख करोड़ के 125 एमओयू भूमि पूजन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं, यूपीसीडा के भी एक लाख करोड़ रुपये के एमओयू धरातल पर उतारने के लिए तैयार हैं। हालांकि लक्ष्य के सापेक्ष यूपीसीडा की उपलब्धि भी पचास प्रतिशत के दायरे में सिमटी है।